



आखंड भारत संदेश

www.akhandbharatsandesh.net

नगर संस्करण प्रयागराज

रविवार 1 अक्टूबर 2023

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को दुत्थिति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान आश्रम की अनुपम भेट

प्रयागराज से प्रकाशित

अब सात अक्टूबर तक बदल और जमा कर सकेंगे दो हजार के नोट

3.56 लाख करोड़ रुपये के 2000 के बैंक नोटों में से 3.42 लाख करोड़ रुपये के नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं।

3.56 लाख करोड़ रुपये के 2000 के बैंक नोटों में से 3.42 लाख करोड़ रुपये के नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। 29 सितंबर, 2023 को इसकी आधिकारी तारीख यह है। अब तक इसकी आधिकारी तारीख 30 सितंबर, 2023 थी। बता दें कि कुछ महीनों पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो हजार रुपये के नोटों को वापस लेने का एलान किया था। 19 मई 2023 को प्रचलन में रहे ?2000 बैंक नोटों का 96% बैंकों में रह गए हैं। इस प्रकार, 19 मई 2023 को 19 इश्यू दफ्तरों के बाद केवल 0.14 लाख करोड़ रुपये ही चलन में रह गए हैं। इस प्रकार, 19 मई 2023 को प्रचलन में रहे ?2000 बैंक नोटों का 96% बैंकों में रह गया है।

8 अक्टूबर के बाद सिर्फ आरबीआई के 19 इश्यू दफ्तरों से बदले जा सकेंगे नोट। आरबीआई की ओर से जारी बयान में लोटा बैंक से प्राप्त ऑफिसों के अनुसार, 19 मई, 2023 तक प्रचलन में मैं रहे बैंक शाखाओं में दो हजार के नोटों को

जमा लेना और बदलना बंद कर दिया जाएगा। आठ अक्टूबर के बाद आरबीआई के 19 इश्यू दफ्तरों में एक बार में 20 हजार रुपये तक के 2000 के नोट बदले जा सकेंगे।

19 इश्यू दफ्तरों के माध्यम से खालों में भी जमा हो सकेंगे 2000 के नोट। आठ अक्टूबर के बाद केवल आरबीआई के 19 इश्यू दफ्तरों के माध्यम से दो हजार के बचे नोटों को अपने खालों में जमा किया जा सकता है। लोग दो हजार के नोट डाक विभाग से भी आरबीआई के 19 इश्यू दफ्तरों को भेज सकते हैं। ये नोट का

मूल्य संबंधित व्यक्ति के खाते में क्रेडिट कर दिया जायगा। 2000 रुपये के बैंक नोट वैध बने रहेंगे। आरबीआई की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि सात अक्टूबर के बाद भी 2000 रुपये के बैंक नोट वैध बने रहेंगे। अदालतों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सरकारी विभाग या पब्लिक अथारिटी जिन्होंने किसी सीमा के केंद्रीय बैंक के 19 आरबीआई निर्माण कार्यालयों में से किसी भी 2000 रुपये के बैंक नोट जमा कर सकेंगे।



अब सात अक्टूबर तक बैंक शाखाओं में बदल सकेंगे 2000 के नोट

हर योजना में भ्रष्टाचार हागी है, इसलिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार को हटाने और बीजेपी को लाने के लिए जनता पूरी तरह से तैयार है: मोदी

'छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय'

'भारत सरकार ने निर्भाव अपनी जिम्मेदारी'

पीएम ने कहा उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभायी हुई छत्तीसगढ़ में हजारों रुपये के बैंकों के बाद आरबीआई और पैसे भेज, तो किंतु कांग्रेस सरकार की जगह से यह तो वह रही हुई है या बहुत देरी से शुरू हुए। हर परियोजना में रोक-टोक करने वाली कांग्रेस सरकार अगर यहां पर दोबारा आई तो क्या छत्तीसगढ़ का भला होगा? इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों का जीवन आसान बनाने की कोशिश में जुटी रहती है। उन्होंने कहा कि हमने शौचालय बांधा तो दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों की मुश्तिकरण कर्म द्वारा। हमने सभी शाखायों जो प्रधानमंत्री की अधिकारी की अदालतीय योजना में सुपर बिजली कनेक्शन दिए तो दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों के घर रोशन हुए। हमने उज्जला योजना के तहत मुफ्त कनेक्शन दिया तो इन परिवारों को खुए से मुक्ति मिली। सद्गुरु रहे कि छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान भले ही न हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

बिलासपुर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को बिलासपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ग्रैंड ओल्ड पार्टी 'कांग्रेस' पर जमकर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि हर योजना में ब्राह्मचार रही है, इसलिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार को हटाने और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को लाने के लिए जनता पूरी तरह से तैयार है।

बिलासपुर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली से मैं जितनी भी कोशिश करूँ यहां की कांग्रेस



भाजपा की 'परिवर्तन यात्रा' के समाप्ति में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल विहारी वाजपेयी जी जो छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं को समझते हुए इस प्रदेश का निर्माण किया था। भाजपा ने छत्तीसगढ़ के लोगों के समर्थकों के समझा, यहां का हाई कोर्ट हमारे बिलासपुर में है। उन्होंने कहा, आज मैं यह गांधी देने आया हूं कि आपके सपने को साकार करने के लिए मैं ऊर्ध्व नहीं छोड़ूँगा। जनता का सपना, मेरा का संकल्प है। छत्तीसगढ़ के हर परिवार का सपना तभी साकार होगा, तब छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार होगी।

'कांग्रेस में बची खबरलोंगी'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली से मैं जितनी भी कोशिश करूँ यहां की कांग्रेस



में भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में जाने से रोका

खालिस्तान समर्थकों ने ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में जाने से रोका

एडिनबर्ग खालिस्तान समर्थकों के हाथों से लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। कनाडा में अरजाक माहोल बनाने के बाद अब स्कॉटलैंड में खालिस्तान समर्थकों ने ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त को एक गुरुद्वारे में जाने से रोक दिया। भारत ने इस पर कड़ी अपार्टि जताते हुए किंतु विदेश विद्यालय परिवार के साथ यह मसला उठाया है। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी

स्कॉटलैंड के सबसे बड़े शहर गुरुद्वारे में स्थित गुरुद्वारे में गुरुद्वारा विधायिका के दौरान कालापीपल विधानसभा क्षेत्र अवर्गत ग्राम पोलायकला में आवोजित जन अंत्रिक्षांश यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में जनता जनगणना को लेकर केंद्र साकार और आरबीआई के बाद गुरुद्वारे के पास पहुँचे, गुरुद्वारे के बाद ही खालिस्तान समर्थकों ने उनकी कार को घेर लिया और उन्हें अंदर नहीं आवाजी को लाया। सोलाल मंडिया पर वायरल हो रहे थे जिनका एक वीडियो में खालिस्तान समर्थक गुरुद्वारे

देश के सामने एक ही मुद्दा है, जातीय जनगणना: राहुल

शाजापुर

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष गुरुद्वारे में भासीपाल के समर्थकों के साथ बैठक के दौरान कालापीपल विधानसभा क्षेत्र अवर्गत ग्राम पोलायकला में आवोजित जन अंत्रिक्षांश यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में जनता जनगणना को लेकर केंद्र साकार और आरबीआई के बाद गुरुद्वारे के पास पहुँचे, गुरुद्वारे के बाद ही खालिस्तान समर्थकों ने उनकी कार को घेर लिया और उन्हें अंदर नहीं आवाजी को लाया। इसका बाकी गुरुद्वारे पर वायरल हो रहा है। जिनका एक वीडियो में खालिस्तान समर्थक गुरुद्वारे



जनगणना। ओवीसी अधिकारी कितने हैं? उनकी भागीदारी कितनी होती है? जबकि नरेन्द्र मोदी की ओर से गांधी चाहिए? उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आपे यह पहला काम हम करके दिखाएंगे। उन्होंने महिला अधिकारी की शुरूआत की थी। ये यात्रा की जन अंत्रिक्षांश यात्रा के जवाबदार के बाद गुरुद्वारे में से 26 सितंबर से जन अंत्रिक्षांश यात्रा की आगाज किया गया। गैरतालव है कि नरेन्द्र भाई के प्रदर्शन के साथ अनुसंधान संगठन (इसीरों) का कायाकल्प करने और इसके वैज्ञानिकों को प्रेरित करने के साथ-साथ अलग-अलग ग्रामों में जनगणना की आगाज किया गया।

ओवीसी अधिकारी की जनगणना को देखने के लिए जनगणना की आगाज किया गया।

जनगणना की आ

संपादक की कलम से

महिला आरक्षण विधेयक : शकुनि का पांसा

इस विधेयक के खिलाफ कोई नहीं है। महिलाओं को समानता की मांग करने वाला कभी उन्हें आरक्षण देने के खिलाफ हो भी नहीं सकता। इसकी नियमावली भी बाद में बनाई जा सकती है, लेकिन सवाल यह है कि इतने सालों तक सरकार में रही और संसद के अधिवेशनों में महिला विरोधी कदम उठाने वाली भाजपा को आज अचानक क्यों इस देश की महिलाओं के पक्ष में निर्णय लेने का ख्याल आ गया?

अंतः: वोट कबाड़ने और सत्ता में बने रहने के लिये आखिरी पांसां भी फेंक दिया गया। 'मनुस्मृति' को देश के संविधान से ऊपर मानने वाली, 'संविधान सभा' में हिंदू महिलाओं को अधिकार देने वाले 'हिंदू कोड बिल' के खिलाफ हंगाम करते हुये उसे पारित होने से रोकने वाली महिला विरोधी पलटन ने अंतः: महिला आरक्षण के विधेयकों को 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के नाम से एक पासे की तरह उछाल दिया है। इस विधेयक के खिलाफ कोई नहीं है। महिलाओं को समानता की मांग करने वाला कभी उन्हें आरक्षण देने के खिलाफ होते भी नहीं सकता। इसकी नियमावली भी बाद में बनाई जा सकती है, लेकिन सबाल यह है कि इतने सालों तक सरकार में रही और संसद के अधिवेशनों में महिला विरोधी कदम उठाने वाली भाजपा को आज अचानक क्यों इस देश की महिलाओं के पक्ष में निर्णय लेने का ख्याल आ गया? इसीलिए न कि अब लोकसभा और कई बड़े राज्यों के चुनाव सिर पर हैं। कई महिला संगठन इस विधेयक को पारित करने और महिलाओं को विधायिकाओं में अधिकार देने की कई सालों से मांग कर रहे थे। दिल्ली और देश के कई शहरों, कस्बों और इलाकों में इसकी मांग करते हुये प्रदर्शन हुये, सेमीनार हुये, महिलाओं की बैठकें हुईं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार भी कोई दूध धुली नहीं थी, लेकिन उस वक्त जब यह विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ था तब लोकसभा में इसे पारित करने में अड़ंगे लगाने वाली भाजपा अब क्यों इस विधेयक को पारित करने का दिखावा कर रही है? वैसे किसी भी समाज या देश में बदलाव तभी होते हैं जब आप जनता उनके पक्ष में आवाज बुलांद करती है। देश के प्रगतिशील महिला आदोलनों का ही परिणाम था कि प्रजातांत्रिक परंपराओं और धर्मनिषेक्षता की रक्षा करने के लिये संविधान में संशोधन होते रहे और कानून बनते रहे। 'राष्ट्रीय महिला आयोग' बना और हर राज्य में भी 'महिला आयोग' बने। देश में कामगार महिलाओं की दशा पर सरकार द्वारा एक अध्ययन करवाया गया और महिलाओं के पक्ष में कानून बनाने की कोशिश की गई। दहेज हिंसा को परिभाषित करते हुये 498 ए जैसा कानून बना, देश में घरेलू हिंसा को रोकने के लिये अलग कानून बनाया गया, कार्यस्थल पर यौन हिंसा के खिलाफ कानून बना, यौन हिंसा की परिभाषा विस्तृत की गई, पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद उन्हें प्रशिक्षित किया गया और अब कई पंचायतों में महिलायें आधे से भी अधिक चुनी गई हैं। माना कि इन तमाम कानूनों में कई खामियां हैं, लेकिन इन खामियों को दूर करने के लिये आवाज उठाई जा रही है। कुल मिलाकर आज नहीं तो कल महिला आरक्षण विधेयक पारित होना ही था। जो भाजपा हर साल हजारों महिलाओं की जान लेने वाले दहेज अपराध को रोकने के लिये बने 498 ए कानून को कमज़ोर करने में लगी हो, वह कैसे इस कानून को बनायेगी और महिलाओं को विधायिकाओं में पहुंचने का रस्ता साफ करेगी।

आर.के.सिन्हा
महात्मा गांधी को विद्यार्थियों से मिलना-जुलना और उनसे बातें करना पसंद था। वे स्कूलों, कॉलेजों और विश्व विद्यालयों में भी अक्सर जाते थे। वे एक बार मास्टर जी की भी भूमिका में आ गए थे। वे पहली बार 12 मार्च 1915 को राजधानी दिल्ली आए तो सेंट स्टीफंस कॉलेज में ठहरे। वे वहां पर छात्रों और फेकल्टी से भी मिले। उनके साथ सामयिक सवालों पर लंबी चर्चाएँ की। दरअसल उन्हें दिल्ली प्रवास के दौरान सेंट स्टीफंस कॉलेज में रुकने का आग्रह उनके करीबी सहयोगी दीनबंधु सी.एफ.एंड्र्यूज ने किया था। दीनबंधु एंड्र्यूज उसी दिल्ली ब्रदरहुड सोसायटी से जुड़ हुए थे जिसने सेंट स्टीफंस कॉलेज और सेंट स्टीफंस अस्पताल की स्थापना की थी। यहां के छात्रों पर गांधी जी और एंड्र्यूज का असर न हो यह नहीं हो सकता। यहां की दोवारों पर अभी भी गांधीजी और एंड्र्यूज के चित्र टैग हैं। सेंट स्टीफंस कॉलेज की स्थापना दिल्ली में ब्रदरहुड ऑफ दि एसेन्डेंड क्राइस्ट ने सन 1877 में हुई थी। अब इसे दिल्ली ब्रदरहुड सोसायटी कहा जाता है। दिल्ली ब्रदरहुड सोसायटी के फादर सोलोमन बताते हैं कि सेंट स्टीफंस कॉलेज को भले ही ब्रिटेन की एक मिशनरी ने शुरू किया पर इसकी भारत तथा यहां के लोगों के प्रति निष्ठा और समर्पण असरदार रहा। दीनबंधु एंड्र्यूज ब्रिटिश नागरिक होते हुए भी भारत की आजादी के प्रबल पक्षधर थे। इसी से अंदाजा लग जाएगा कि सेंट स्टीफंस कॉलेज को खोलने वाली संस्था का मूल चरित्र किस तरह का है। गांधी जी यहां 1918 तक रहे। उन्हें यहां पर ब्रजकृष्ण चांदीवाला नाम के एक छात्र मिले जो आगे चलकर उनके पुत्रवत हो गए। उन्होंने ही गांधी जी की मृत्यु के बाद अंतिम बार स्नान करवाया था। गांधीजी का काशी से भी गहरा लगाव था। वे अपने जीवनकाल में 12 बार काशी आए। अपना पहला राजनीतिक उद्घोषण गांधीजी ने 5 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था।



जा रहा था। साथ में बीएचयू के संस्थापक पं. मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेट, दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह के साथ कई रियासतों के राजा वहाँ मौजूद थे। गुजराती वेशभूषा (धोती, पगड़ी और लाठी) में आए गांधीजी ने मंच से लोगों के सामने तीन बारें रखी थीं। गांधीजी ने कहा था- हृदय की जनता, छात्र और आप सभी भारत का स्वराज कैसा चाहते हैं? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लोग स्वराज को लेकर क्या सोचते हैं, यह स्पष्ट होना चाहिए? इसी बीच गांधीजी की नजर वहाँ मौजूद राजाओं के आभूषणों पर पड़ी। उन्होंने कहा- अब समझ में आया कि हमारा देश सोने की चिड़िया से गरीब कैसे हो गया? आप सभी को अपने स्वर्ण जड़ित आभूषणों को बेचकर देश के जनता की

जानकारी भी थी मास्टर जी के में उनकी पाट छात्रों को अंग उनकी कक्षाओं में थे। उसमें ब राजधानी के 214 दिन रहे जून, 1947 त सटी वाल्मीकी के बच्चों को खासी भीड़ हे विवार्थियों को कक्षा में सफानहीं आते थे। देते थे। वे माआप शुद्ध ज्ञान

वाल्मीकी बस्ती से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत
अभियान की भी शुरूआत की थी।
बहरहाल वह कमरा जहां पर बापू पढ़ा
थे, अब भी पहले की तरह ही बना हुआ
है। इधर एक चित्र रखा है, जिसमें कुछ
बच्चे उनके पैरों से लिपटे नजर आते हैं।
आपको इस तरह का चित्र शायद ही कभी
देखने को मिले। बापू की कोशिश रहती है,
कि जिन्हें कर्तव्य लिखना-पढ़ना नहीं आता,
वे भी कठ लिख-पढ़ सकें। इस वाल्मीकि
मंदिर में बापू से विचार-विमर्श करने वाले
लिए पड़िए नेहरू से लेकर सीमांत मांगने
खान अब्दुल गफ्फार खान भी आते हैं।
सीमांत मांगनी यहां बापू के साथ कई बार
ठहरे भी थे। अब भी इधर बापू के कक्ष के
दर्शन करने के लिए देखने वाले आते रहे।

हैं। वाल्मीकी समाज की तरफ से प्रयास हो रहे हैं कि इधर गांधी शोध केन्द्र की स्थापना हो जाए। गांधी जी की संभवतः महानतम जीवनी ह्यादि लाइफ आफ महात्मा गांधील के लेखक लुई फिशर भी उनसे वाल्मीकी मंदिर में ही मिलते थे। वे 25 जून, 1946 को दिल्ली आए तो वहां पर बापू से मिलने पहुंचे थे। उस समय इधर प्रार्थना सभा की तैयारियां चल रही थीं। ह्यादि लाइफ आफ महात्मा गांधील को आधार बनाकर ही फिल्म गांधी का निर्माण हुआ था। यही नहीं, गांधी जी के आशीर्वाद से ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्थापित हुई। वे इसके पहले करारल बाग और फिर ओखलांग के परिसरों में कई बार गए थी। महात्मा गांधी ने अगस्त 1920 में, असहयोग आंदोलन का ऐलान करते हुए भारतवासियों से ब्रिटिश शैक्षणिक व्यवस्था और संस्थानों का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। गांधी जी के आह्वान पर, उस समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ अध्यापकों और छात्रों ने 29 अक्टूबर 1920 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद रखी। बाद में जामिया, अलीगढ़ से दिल्ली स्थानान्तरित हो गया। ब्रिटिश शिक्षा और व्यवस्था के विरोध में बने, जामिया मिल्लिया इस्लामिया को धन और संसाधनों की बहुत कमी रहती थी। रजवाड़े और पैसे वाले लोग, अंग्रेजी हुक्मत के डर से इसकी आर्थिक मदद करने से करतरते थे। इसके चलते 1925 के बाद से ही यह बड़ी आर्थिक तंगी में घिर गया। ऐसा लगने लगा कि यह बंद हो जाएगा। लेकिन गांधी जी ने कहा कि कितनी भी मुश्किल आए, स्वदेशी शिक्षा के पैरोकार, जामिया को किसी कीमत पर बंद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, ह्याजामिया के लिए अगर मुझे भीख भी मांगनी पड़े तो मैं भीख मांगूँगा हाँ गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी ने जामिया में एक शिक्षक के रूप में काम किया। गांधी जी के पाते परिकलाल ने भी जामिया में पढ़ाई की। यह जरूरी है कि देश गांधी जी के व्यक्तित्व के इस पक्ष को भी जाने की वे छात्रों और नौजवानों के बीच में जाना पसंद करते थे।

क्यों बापु पसंद करते थे विद्यार्थियों से मिलना

भारत कनाडा मामले में अमेरिकी रुख पर दुनिया की नजरें

सम्मेलन दिल्ली घोषणापत्र, कुछल भारतीय नेतृत्व, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बढ़ता जनसमर्थन, हर क्षेत्र में चौमुखी विकास सहित अनेक मुद्दों पर भारत की दस्तक महसुस की जा रही है, जिससे भारत की बास और आँटोग्राफ की उपाधि सिद्ध होते जा रही है बड़े बुजुर्गों का कहना है कि घी गोदड़ी में छुपाकर खाना चाहिए वरना ज्वलेसी रूपी नाग से भिड़त होते हुए कमजार होने और सफलता फिसल जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हम अनेक क्षेत्रों चाहे वह व्यापार व्यवसाय तकनीकी प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में देखते हैं कि आपसी ज्वलेसी के चलते कंपटीन, टांग खींचना जैसे कृत्य शुरू हो जाते हैं। वैसे अगर हम इस परिपेक्ष में वर्तमान नए भारत, दबंग प्रतिष्ठित बुलंद भारत को देखें तो स्वाभाविक है, सफलता में उन देशों को मजा ना आता हो और सामने होकर यारी दिलदारी और पीछे टांग खींचने की बारी से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज हर देश अपना ओहदा उच्चपद रुतबा खोना नहीं चाहता इसके लिए यदि वह सामने से कुछ नहीं कर सकता तो, पर्दे के पीछे कुछ संभावनाएं बढ़ जाती हैं। परंतु सच तो सामने आकर ही रहता है, अगर भारत सच्चा है तो हमारे में कहावत है सचु त बीठा नचु यानें अगर हमसच्चे हैं तो भरे बाजार में लोगों के बीच अपनी सच्चाई का सबूत देकर खुशी से नाच सकते हैं। आज यह विषय हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि भारत के रिश्ते अब तक पड़ोसी और विस्तारवादी देश से तल्खी में थे, परंतु विगत कुछ दिनों से कनाडा के साथ तल्खी

जरूरी है, क्योंकि यह स्थिति जानबूझकर उठाइ गई है या स्वाभाविक है इसे देखने की जरूरत है, क्योंकि कनाडा फाइव आइस, जी 7 का सदस्य है, तो अमेरिका हमारा अल्पत करीबी देस्त है, जिसके लिए परीक्षा की घड़ी है कि इस मुद्दे को मिलकर सुलझाने की चेष्टा करें, क्योंकि भारत पश्चिमी देशों का सदस्य नहीं है परंतु पश्चिम से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। परंतु दबी जबान से यह बात सामने आ रही है कि 28 सितंबर 2023 को वॉशिंगटन डीसी में भारत अमेरिका विदेश मंत्रियों की बैठक में अमेरिका ने इस मुद्दे को उठाया है, जिसे बाहरी तौर पर साफ इनकार किया जा रहा है, परंतु मॉटर्सेशियल में कनाडा पीएम द्वारा भारत की तरीफ और अमेरिका द्वारा विदेश मंत्रियों की बैठक में मुद्दा उठाने की गंतव्यी वाली बात कह कर इसपर बल दिया है और रणनीति कूटनीति की बूरही है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, कनाडा प्रकरण में अमेरिका की भूमिका, भारत को बेहद सर्तक रहने को रेखांकित करना जरूरी है।

साथियों बात अगर हम 28 सितंबर 2023 को वॉशिंगटन डीसी में भारत अमेरिका विदेश मंत्रियों की बैठक की करें, तो, संभावना जर्ताई जा रही है कि, अमेरिका के विदेश मंत्री ने गुरुवार को समक्ष के साथ मीटिंग के बक्स निज्जर की हत्या का मुद्दा उठाया। रॉयटर्स के मुताबिक, एक अमेरिकी अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की। अधिकारी ने बताया- उन्होंने भारत सरकार से मामले की जांच में सहयोग करने के लिए कहा

से किसी ने भी प्रेसवार्ता में मुलाकात का एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया। हालांकि एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि इस दैरण कनाडा के पीएम के लगाए आरोपों का मामला विदेशमंत्री ने सामने रखा। मैटिया में रिपोर्ट के अनुसार, नाम न बताए जाने की शर्त पर अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ब्लिंकन ने भारत को कनाडाई जांच में सहयोग करने का आश्वासन दिया है। वहाँ विदेश विभाग के प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर भारत सरकार के साथ लगातार बातचीत और उनसे सहयोग करने का आग्रह किया है।

गैरतलब है कि इससे पहले विदेश मंत्री ने बीते दिनों कनाडा के आरोपों पर सबूत देने की बात कही थी। उन्होंने कनाडाई पीएम के आरोपों पर कहा था कि अगर आपके पास विशिष्ट जानकारी है, अगर आपके पास कुछ प्रासारिक है, तो हमें बताएं। हम इसे देखने को तैयार हैं। वे आगे ये भी बोले कि अभी तस्वीर पूरी बन नहीं पा रही है क्योंकि संदर्भ का पता नहीं। इसके साथ ही उन्होंने आईना दिखाए हुए ये भी कहा था कि राजनीतिक कारणों से खालिसानियों के प्रतिकानाडा काफी उदार है। साथ ही वह इस दैरण कनाडा में भारतीय राजनियों को मिलने वाली धमकी और भारतीय वाणिज्य दूतावासों पर हमलों पर भी चिंता जताई थीं।

साथियों बात अगर हम अमेरिका की करें तो, जहाँ एक तरफ चीन के डर के कारण भारत के साथमजबूत सामरिक संबंध बनाना चाहता है तो वहाँ दूसरी तरफ भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाले आतंकवादी तत्वों को पनाह

नहीं किया जा सकता। अमेरिका दशकों तक भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान का भी इसी तरह से इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन भारत बदल रहा है और अब समय आ गया है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को यह साफ-साफ बता दिया जाए कि सामरिक सांझेदारी, व्यापार और अर्थिक समझौता भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है लेकिन यह भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता से बढ़कर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और यह बात अमेरिका और उसके सहयोगी देश जितनी जल्दी समझ ले उतना ही यह विश्व की शाति के लिए बहतर होगा। चीन की आक्रामक नीति से परेशान अमेरिका एक तरफ जहां भारत को अपने एक मददगार देश के तौर पर देख रहा है, दोनों ही देश चीन की आक्रामक नीतियों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, संयुक्त सैन्याभ्यास कर चीन को संकेत दे रहे हैं, अर्थिक मोर्चे पर लगातार नए-नए समझौते कर आर्थिक संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। यहां तक कि रक्षा क्षेत्र में भी कई विकल्प होने के बावजूद भारत अमेरिका के साथ रक्षा समझौते कर उसकी अर्थव्यवस्था को मदद देने का काम कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की चुप्पी ने भारत को सतर्क कर दिया है निजर हत्याकांड में कनाडा द्वारा लगाए गए बेरुते के आरोप की वजह से भारत और कनाडा के रिश्तों पर तो बुरा असर पड़ ही रहा है लेकिन इस पूरे मामले में कई जानकारी के सामने आने के बाद अब अमेरिका के रुख को भी लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। साथियों बात अगर हम कनाडाई पीएम का

पीएम ने कहा कि उन्हें अमेरिका से आश्वासन मिला है कि विदेश मंत्री गुरुवार को वाशिंगटन में भारतीय विदेश मंत्री के साथ बैठक के दौरान निज्जर हत्या में भारत की भूमिका के बारे में सार्वजनिक रूप से लगाए गए आरोपों को उठाएँगे। मीडिया के मुताबिक, पीएम ने कहा कि अमेरिका भारत सरकार से बात करने में हमारे साथ रहा है। उन्होंने कहा, यह कुछ ऐसा है जिसे सभी लोकतात्रिक देशों और कानून के शासन का सम्मान करने वाले सभी देशों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। आगे कहा, हम भारत सरकार के प्रति अपने विटिकोण सहित अपने सभी साझेदारों के साथ कानून के शासन में रहते हुए एकविचारशील जिम्मेदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा, भारत एक बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति और महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक खिलाड़ी है। जैसा कि हमने पिछलो साल अपनी इडो-पैसिफिक रणनीति में कहा था कि हम भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने को लेकर बहुत गंभीर हैं। जाहिर तौर पर कानून के शासन वाले देश के रूप में, हमें इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए कनाडा के साथ काम करने की जरूरत है कि हमें निज्जर के मामले के पूरे तथ्य मिलें। कनाडा के पीएम ने भारत से गतिरोध के बीच कहा है कि कनाडा अभी भी भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक बार फिर कथित आरोपों को लेकर कहा कि खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता के

भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए तिबद्ध है। भारत के दुनिया भर में बढ़ते प्रभावी और इशारा करते हुए टूटो ने कहा कि यह हुत महत्वपूर्ण है कि कनाडा और उसके हयोगी भारत के साथ जुड़े रहें। मॉन्ट्रियल में एक स काफ़ेंस में बोलते हुए टूटो ने कहा कि उन्हें आगता है कि यह बेहद महत्वपूर्ण है कि कनाडा और उसके सहयोगी विश्व मंच पर भारत के बढ़ते हत्या को देखते हुए उसके साथ रचनात्मक और भीरता से जुड़ते रहें। उन्होंने ये भी कहा कि साथ कानून के शासन वाले देश के रूप में हम बहते हैं कि भारत, कनाडा के साथ मिलकर काम करें, आगे कहा कि अमेरिका हमारे साथ है और ह भारत के सामने कनाडा की धरती पर कनाडाई नागरिक की हत्या के मामले को उठा रहा। आगे कहा कि सभी लोकतांत्रिक देश चाहते हैं, कि सभी देश उनके कानून का सम्मान करें और से संभीरता से लें। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे वरण का अध्ययन कर इसका विशेषण करें तो य पाएंगे कि भारतअमेरिका यारीकनाडा मामले और कूटनीतिक हल निकालने की बारी भारत कनाडा मामले में अमेरिकी रुख पर दुनियां की जरें कनाडा प्रकरण में अमेरिका की भूमिका - भारत को बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता को खोकित करना जरूरी

संकलनकर्ता लेखक - कर विशेषज्ञ स्तंभकार डवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोदिया हाराष्ट्र

जिसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, यह था। वह बयान भी इस मामले को और है और इससे नेतृत्व को शॉक लगना कार्रा

ससद न बनाइ
निकलने का एक

भाजपा नेतृत्व माफी मांग सकता है, प्रधानमंत्री सहित उसके वरिष्ठ नेता दानिश अली से मिल सकते हैं और उन्हें तथा राष्ट्र को आशयस्त कर सकते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा एवं अपमानित करने वाले को उचित सजा जा जाएगी। भाजपा में शामिल और पार्टी के समर्थक लोगों में से कितने लोग सोचते हैं कि ऐसा रास्ता संभव है, वांछीय है और यहा तक कि भाजपा के लिए लाभदायक भी है? दक्षिण दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिहुड़ी द्वारा बसपा सांसद कुंवर दानिश अली के खिलाफ कहे गए अपमानजनक और संप्रदायिक अपशद ऐसी भाषा है जो सदकों पर भी कही जाने योग्य नहीं है और

भाषा सत्ता पर का जार संसद में बोला जा रही है। इस तरह की भाषा बहस के स्तर की गिरावट का प्रतिनिधित्व करती है। इस स्तर पर भाजपा प्रतिस्पर्धी सांग्रहायिकता और ध्यान आकर्षित करने की बीमारी में फंस गई है। इसके कुछ महत्वाकांक्षी सदस्य खतरनाक तरीकों से मंच हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहूड़ी के खिलाफ कड़ी और त्वरित कार्रवाई की कमी इस तरह के दुरुपयोग को वैध बनाती है। यह वास्तव में दूसरों को संदेश देती है कि इस कीड़ा भी खेलना और 2024 के चुनावों की तैयारी के दौरान सांग्रहायिक धृणा के बढ़ते प्रसार में योगदान देना ठीक है। इसका हालिया उदाहरण भाजपा के एक अन्य सांसद का यह दावा है कि बिहूड़ी को उकसाया गया

लाप्रकाशक बनाने का एक प्रयत्न है कि अकथरीय और उग्र शब्द उस वर्तन के जब वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का करते हुए दिखाई दिए। इसे संपरिस्थितियों में और आदर्श रूप से प्रधानमंत्री के अपमान के रूप में जाना चाहिए।

आरोप का जवाब तेरे अन्य तरीके भी है। विवाद उस समझ हुआ जब प्रधानमंत्री ने चन्द्रमा मिशन के लिए इसरो को देने के बजाय इसका खुद लिया। आपल्बों का प्रयोग आरोपों का खंडन करने से कोई फायदा नहीं होता है बल्कि इससे आरोपों का साबित होते हैं। आरोपों के गुण-दोष परवाह न करते हुए देखें तो ऐसी ही से प्रधानमंत्री और पार्टी को नकसा लगता है।

बड़ूआ हाइ। इसके जलपान बिघुड़ा न अपना असश्यतापूर्ण हक्रत से संसद के नए भवन में संसद के पहले सत्र को ही अपवित्र कर दिया जिसे भाजपा अपनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में पेश कर रही थी। बिघुड़ी ने भाजपा की इस उपलब्धि का अपहरण कर लिया है। खुद प्रधानमंत्री ने संसद की नई इमारत को 'सिर्फ' एक नई इमारत नहीं बल्कि एक नई 'शुरुआत' का प्रतीक' कहा है। बिघुड़ी ने उस 'नई शुरुआत' को एक बहुत ही अशुभ अर्थ दे दिया। उहोंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण विधेयक से भी ध्यान हटा दिया जिसे प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक कानून तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला कहा था। बिघुड़ी की टिप्पणी उन पर कही

परिणाम बताता नास्ट जारी होन के बाद रविवार रात तक बिहूड़ी पर कारवाई न होना कई सवाल खड़ करता है। इसमें मुख्य बात भाजपा की नई प्रकृति और चरित्र ही होना चाहिए वयोंके वह 2024 का बुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। भाजपा को पूरा भरोसा है कि वह सत्ता में वापसी करेगी परन्तु ऐसा नहीं है कि उसे राहुल गांधी की ओर से मिलने वाले 'सरप्राईज़' को लेकर कोई चिंता नहीं होगी। विषय की एकजुटता को भले ही कुछ लोग एकजुट उपस्थिति के बजाय एक पैदवर्क समाधान के रूप में खारिज कर रहे हैं लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस एकजुटता ने भाजपा को चिंता में डाल दिया है। सत्ता-विरोधी एक मजबूत लहर भी चल रही है।

दिवस, प्रादृ दिवस अथवा
भी कहा जाता है, प्रयोक्त वर्ष
मनाया जाता है। यह दिवस
गरिकों का सम्मान करने,
को सुखद बनाने एवं उनके
न करने के लिये मनाया
का वृद्ध समाज अत्यधिक
उपेक्षित है और सामान्यतः
व्याधिक दुःखी है कि जीवन
भव होने के बावजूद कोई
लोगों लेना चाहता है और न ही
महत्व ही देता है। इस प्रकार
समाज में एक तरह से
झड़े जाने के कारण हमारा
सर्वाधिक उपेक्षित, दुःखी,
है। वृद्ध समाज को इस दुःख
छत्कारा दिलाना आज की

तांत्रिक हो रहे करने के क्लाने के संदर्भ में अपवाहन की दृष्टि वाले इसी दुनिया में जल्दी की गयी बदलावों की विवरणों की विशेषता, विस्तार से प्रतिकूलताओं ने जम्म लिया है, उन्हीं में से एक है वृद्धों की उपेक्षा। वस्तुतः वृद्धावस्था तो ऐसे भी अनेक शारीरिक व्याधियों, मानसिक तनावों और अन्यान्य व्यथाओं भरा जीवन होता है और अगर उस पर परिवार के सदस्य, विशेषतः युवा परिवार के बुजुर्गों/वृद्धों को अपमानित करें, उनका ध्यान न रखें या उन्हें मानसिक सताप पहुंचाएं, तो स्वाभाविक है कि वृद्ध के लिए वृद्धावस्था अभिशाप बन जाती है। इसलिए तो मनुसमृद्धि में कहा गया है कि-**ज्ञज्ञ
मनुष्य यह देखे कि उसके शरीर की त्वचा शिथिल या ढीली पड़ गई है, बाल पक्का गए हैं, पुत्र के भी पुत्र हो गए हैं, तब उसे सासारिक सुखों को छोड़कर वन का आश्रय ले लेना चाहिए।**

